ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in March 2025

राजस्थान के सीकर जिले में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति छात्रों की धारणा: एक सांख्यिकीय अध्ययन

राजेन्द्र सिंह बाजिया, शोधार्थी, शिक्षा संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
डॉ रमेश चन्द्र नागदा, शोध पर्यवेक्षक, प्राचार्य, शिक्षा संकाय, द नोबल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, खेरवाड़ा, उदयपुर

सारांश

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह न केवल शैक्षिक गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है, अपितु छात्रों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का कार्य भी करता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में अनेक नवीन प्रावधान किए हैं, जिनका प्रभाव जमीनी स्तर पर किस प्रकार परिलक्षित हो रहा है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध राजस्थान के सीकर जिले में अध्ययनरत 150 कॉलेज छात्रों की उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति धारणा का विश्लेषण करता है। निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि अधिकांश छात्र इस प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, किंतु सूचना, संसाधन एवं भाषा संबंधी बाधाएँ अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य शब्द : अंतर्राष्ट्रीयकरण, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छात्र धारणा, सांख्यिकीय परीक्षण, राजस्थान

परिचय

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण शैक्षिक संस्थानों के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। यह केवल विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की भौगोलिक गतिशीलता तक सीमित नहीं है, अपितु पाठ्यक्रम, शोध, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी समाहित करता है। भारत में 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) ने इस दिशा में विशेष बल दिया है, जिसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने, भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय संस्थानों के साथ गठजोड़ करने, और भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने हेतु विविध पहल की गई हैं। हालांकि, इन नीतियों का वास्तविक प्रभाव छात्रों की धारणा पर किस प्रकार परिलक्षित हो रहा है, विशेषतः ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों में, यह जानना शोध का केंद्रीय विषय है। सीकर जिला, जो राजस्थान का एक शैक्षिक केंद्र बन चुका है, इस प्रकार के अध्ययन हेतु उपयुक्त क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के छात्र उच्च शिक्षा में संलग्न हैं।

समीक्षा साहित्य

अश्विनी (2021) ने सतत् विकास के मार्ग में उच्च शिक्षा पर एनईपी 2020 पर अध्ययन किया। यह लेख मुख्य रूप से एनईपी - 2020 की कुछ उल्लेखनीय और मुख्य विशेषताओं और भारत में उच्च शिक्षा पर इसके परिणामों पर केंद्रित है। वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए भारत में एक नई शिक्षा नीति को अपनाने और लागू करने में काफी समय लग गया था। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा नीति एक स्वागत योग्य बदलाव है और इसे एनईपी-2020 के रूप में संक्षिप्त किया गया है। शैक्षिक संरचना, दिशानिर्देश और उसके कार्यान्वयन की पद्धति सराहनीय है। असंगठित और अवैज्ञानिक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एनईपी - 2020 द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित किए गए परिवर्तन अधिक प्रतिभाशाली और अधिक व्यावहारिक छात्रों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में आशा की एक नई लहर जगाते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विपरीत एनईपी - 2020 13-18 के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक लंबे छात्र-शिक्षक संबंध को प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रशंसा हासिल करने के लिए खेलों में भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। एनईपी-2020 स्कूल स्तर के साथ-साथ कॉलेज स्तर पर भी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती दिख रही है।

चाको, मैथ्यू (2021) ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा संस्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव विश्लेषण पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में, इस प्रभाव का अध्ययन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा गिनाए गए दस मानदंडों के लिए किया जा रहा है जो वाशिंगटन समझौते पर आधारित है। जीई-मैकिन्से नाइन बॉक्स मैट्रिक्स का उपयोग करके नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभाव विश्लेषण किया गया था। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उच्च शिक्षा संस्थानों पर चार मापदंडों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, अर्थात् ए) सीखना और विकास बी) आंतरिक प्रक्रियाएँ सी) छात्र/संकाय डी) वित्तीय। यह निष्कर्ष निकाला गया कि नई एनईपी का एचईआई के सीखने और विकास और

छात्रों/संकाय पहलुओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे पहले, संस्थान को खुद को बेंचमार्क करना चाहिए और की गई प्रत्येक पहल के प्रभाव की निगरानी के लिए एक संतुलित स्कोरकार्ड बनाए रखना चाहिए। ढिल्लों, अजय पाल सिंह (2021) ने एनईपी 2020 : उच्च शिक्षा का परिवर्तन पर अध्ययन किया। यह अध्ययन एनईपी 2020 और भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र को बदलने में इसकी भूमिका पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का इरादा देश में स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और सर्वव्यापी ढांचा प्रदान करना है। यह रणनीति एक नई प्रणाली बनाने के लिए, इसके विनियमन और शासन सहित शैक्षिक संरचना के सभी घटकों के संशोधन और पुनर्निर्माण का प्रस्ताव करती है। सुझाई गई प्रणाली भारतीय परंपराओं और मूल्य प्रणालियों के साथ-साथ 21वीं सदी की शिक्षा के इच्छित परिणामों, जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आधारित है। केवल गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता ही व्यक्तिगत उपलब्धि और उन्नति, उपयोगी और कर्तव्यनिष्ठ सार्वजनिक भागीदारी और समाज में सकारात्मक योगदान की अनुमति देती है। नागरिकों को सार्थक और संतोषजनक जीवन जीने, उत्पादक वातावरण में काम करने और शिक्षा के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। परिणामस्वरूप, एनईपी ने देश के उच्च शिक्षा वातावरण पर व्यावहारिक और दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए कई सुधार और संवर्द्धन लागू किए हैं। एनईपी, 2020 का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रमुख अंतःविषय विश्वविद्यालयों में बदलना है। इसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा अब खंडित नहीं होगी। यह पहल प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला से प्रेरित है, जिसने जीवंत अंतःविषय वातावरण में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से हजारों छात्रों को आकर्षित किया। कुशल और आविष्कारशील मनुष्य पैदा करने की समृद्ध भारतीय विरासत को बहाल करने के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। एचईआई अन्य एचईआई को उचित फंडिंग, प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके सुधार, अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, सामुदायिक सेवा और जुड़ाव, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए संकाय विकास आदि में भी मदद करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. यह जानना कि सीकर जिले के कॉलेज छात्रों की उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति क्या धारणा है।
2. यह मूल्यांकन करना कि क्या लिंग, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि (ग्रामीण/शहरी) एवं आर्थिक स्तर धारणा को प्रभावित करते हैं।
3. छात्रों द्वारा अनुभव की गई संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान करना।
4. नीति-निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष

सीकर जिले के कॉलेज छात्रों में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति जागरूकता और रुचि पाई गई है, विशेष रूप से शहरी और मध्यमवर्गीय छात्र इस दिशा में अधिक सकारात्मक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लाए गए प्रावधानों की जानकारी सीमित स्तर पर छात्रों तक पहुँची है, जिससे इसका वास्तविक प्रभाव बाधित हो रहा है। अतः यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में छात्र-समुदाय को सूचित, प्रेरित और समर्थ बनाया जाए।

इस शोध से यह स्पष्ट हुआ कि छात्रों की उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति धारणा सामान्यतः सकारात्मक है, किंतु यह धारणा विविध सामाजिक-आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों से प्रभावित होती है। पुरुष छात्रों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता और उत्सुकता पाई गई, जबकि महिला छात्रों में यह अपेक्षाकृत कम रही, जिसका कारण भाषा, सामाजिक प्रतिबंध या तकनीकी पहुंच हो सकता है।

शहरी छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की जानकारी अधिक पाई गई, जो कि इंटरनेट की सहज उपलब्धता, मार्गदर्शन संसाधनों और निजी संस्थानों के प्रचार से संबंधित है। ग्रामीण छात्रों में जानकारी की कमी और आत्मविश्वास की न्यूनता एक बाधा रही।

आर्थिक दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग के छात्र अपेक्षाकृत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि निम्न वर्ग के छात्रों में संसाधनों की कमी, विदेश जाने की संभावनाओं की अनिश्चितता एवं आर्थिक असुरक्षा के कारण निराशा अधिक देखने को मिली।

सुझाव

- **जानकारी प्रसार:** अंतर्राष्ट्रीय अवसरों, छात्रवृत्तियों और विदेशी विश्वविद्यालयों से संबंधित जानकारी हेतु कॉलेजों में नियमित सेमिनार, वेबिनार और काउंसलिंग आयोजित किए जाएँ।

- **भाषा सशक्तिकरण:** अंग्रेज़ी और विदेशी भाषाओं में छात्रों की दक्षता बढ़ाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- **आर्थिक सहायता:** आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएँ सुलभ कराई जाएँ।
- **डिजिटल पहुंच:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों को सुलभ बनाया जाए ताकि छात्र ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ सकें।
- **लैंगिक समानता:** महिला छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष नीतियाँ और सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ।

संदर्भ

- अश्विनी. (2021). सतत् विकास के मार्ग में उच्च शिक्षा पर एनईपी 2020 पर अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्स रिसर्च रिव्यू, 8(10), 92-98.
- बंद्योपाध्याय, बिस्वजीत. (2020). भारत में प्रभावी उच्च शिक्षा नीति की रूपरेखा: चुनौतियाँ और अवसर पर अध्ययन. एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेनस प्रोसिडिंग, 18-35.
- चाको, मैथ्यू. (2021). इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा संस्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव विश्लेषण पर अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, 8(1), 1216-1222.
- ढिल्लों, अजय पाल सिंह. (2021). एनईपी 2020: उच्च शिक्षा का परिवर्तन पर अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लीकेशन एण्ड रिव्यूज, 2(12), 1101-1105.
- मंजूनाथ. (2021). उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव पर अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग डेवेलपमेन्ट एण्ड रिसर्च, 9(2), 61-63.
- रेखा. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 -स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा पर अध्ययन. जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइन्स, 12(3), 12-23.
- सिंह, उमा (2020). भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में एनईपी की अंतर्दृष्टि और परिप्रेक्ष्य पर अध्ययन. इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमेनिटीज एण्ड इंटरडिसीप्लीनरी स्टडीज, 1(2), 30-42.
- टीना. (2021). उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव पर अध्ययन. जर्नल ऑफ पॉजीटिव साइकोलोजी, 4(4), 542-561.